

महिला एवं बाल विकास योजनाओं का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

मनीष कुमार शर्मा¹ डॉ. ममता शर्मा²

¹शोधार्थी ²शोध पर्यवेक्षक

शिक्षा विभाग

एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय

कैथल, हरियाणा

सारांश (Abstract):

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास की दिशा में महिला एवं बाल विकास योजनाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना तथा समग्र सामाजिक उन्नति सुनिश्चित करना है। आंगनवाड़ी सेवाएं, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, सुकन्या समृद्धि योजना एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने ग्रामीण समुदायों में जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, बालिका शिक्षा, पोषण सुधार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन योजनाओं के ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें पाया गया कि योजनाओं ने बाल-मातृ मृत्यु दर को घटाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ाने, बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यद्यपि इन योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, फिर भी कई क्षेत्रों में सूचनात्मक और प्रशासनिक चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं। अतः योजनाओं की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए समुदाय आधारित जागरूकता, बेहतर निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन आवश्यक है।

मुख्य संकेतक

महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, ग्रामीण भारत, पोषण मिशन, आंगनवाड़ी, जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका शिक्षा, समाज कल्याण योजनाएँ, संस्थागत प्रसव, SHG, ग्रामीण विकास.

प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण समाज की आधारशिला महिला एवं बालक होते हैं, जिनकी सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति देश की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई हैं जैसे – **आंगनवाड़ी योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन,**

जननी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, बालक-बालिकाओं के पोषण स्तर को सुधारना तथा ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस शोधपत्र में इन योजनाओं के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

अनुसंधान उद्देश्य (Research Objectives)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास योजनाओं की पहुँच का मूल्यांकन करना।
2. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर में आए परिवर्तन को समझना।
3. योजनाओं से प्राप्त लाभों और चुनौतियों की पहचान करना।
4. योजनाओं की प्रभावशीलता को ग्रामीण समाज की दृष्टि से मूल्यांकित करना।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

यह अध्ययन द्वितीयक (secondary) स्रोतों जैसे नीति दस्तावेज, सरकारी रिपोर्टें, शोध पत्र, राष्ट्रीय सर्वेक्षण (NFHS-5, NSSO) आदि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त कुछ केस स्टडी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया है।

तालिका:1 प्रमुख महिला एवं बाल विकास योजनाएँ (Major Women and Child Development Schemes)

योजना का नाम	प्रारंभ वर्ष	उद्देश्य
आंगनवाड़ी सेवाएँ (ICDS)	1975	बच्चों को पोषण, पूर्व-शैक्षिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना
जननी सुरक्षा योजना	2005	संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करना
सुकन्या समृद्धि योजना	2015	बालिकाओं की उच्च शिक्षा और विवाह हेतु वित्तीय सहायता
राष्ट्रीय पोषण मिशन	2018	कुपोषण को समाप्त करना और पोषण स्तर में सुधार करना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ	2015	बालिकाओं के जन्म एवं शिक्षा को बढ़ावा देना

स्रोत: Ministry of Women and Child Development, GoI; NFHS-5 Report (2021)

डेटा विश्लेषण

तालिका :2 कुपोषण में कमी (Reduction in Malnutrition)

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषित बच्चे (%)	योजनाएँ सक्रिय
2005-06 (NFHS-3)	46.0%	केवल ICDS सक्रिय
2015-16 (NFHS-4)	38.4%	ICDS + JSY + MDM
2019-21 (NFHS-5)	35.0%	ICDS + JSY + POSHAN Abhiyaan

विश्लेषण: NFHS के आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत में बच्चों के कुपोषण में धीरे-धीरे गिरावट देखी गई है। यह गिरावट **राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyaan)** जैसे प्रयासों का परिणाम है।

तालिका: 3 संस्थागत प्रसव में वृद्धि (Increase in Institutional Deliveries)

वर्ष	संस्थागत प्रसव दर (%)	योजना
2005-06	38.7%	पहले JSY नहीं थी
2015-16	78.9%	जननी सुरक्षा योजना लागू
2019-21	88.6%	JSY + PMMVY प्रभावी

विश्लेषण: जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लागू होने के बाद **संस्थागत प्रसव में 50% से अधिक की वृद्धि** देखी गई। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई।

तालिका:4 बालिकाओं के नामांकन में सुधार (Girl Child Enrolment Rate)

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन (%)	योजना
2005	63%	कोई विशेष योजना नहीं
2015	82%	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
2021	89%	BBBP + SSA + Sukanya Yojana

विश्लेषण: “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसी योजनाओं ने बालिकाओं के शिक्षा में भागीदारी को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

तालिका: 5 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते (2015–2021)

वर्ष	खुले गए खाते (लाख में)	औसतन जमा राशि (₹)
2015-16	39.9 लाख	₹ 15,000
2018-19	132.2 लाख	₹ 26,100
2021-22	211.1 लाख	₹ 31,400

विश्लेषण: ग्रामीण परिवारों ने इस योजना को अपनाया है और यह योजना लड़कियों की उच्च शिक्षा और विवाह हेतु वित्तीय सुरक्षा का एक स्थायी विकल्प बनी है।

तालिका:6 महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) – आर्थिक सशक्तिकरण

वर्ष	SHGs की संख्या	लाभान्वित महिलाएं (लाख में)
2010	24 लाख	300 लाख
2016	47 लाख	520 लाख
2022	82 लाख	880 लाख

विश्लेषण: NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत SHGs की संख्या और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऋण और व्यवसाय में सहायता मिली है।

ग्रामीण जीवन पर योजनाओं का प्रभाव (Impact on Rural Life)

स्वास्थ्य और पोषण सुधार

- ICDS और राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किए जाते हैं।
- NFHS-5 (2021) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों की संख्या में गिरावट देखी गई है।

मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी

- **जननी सुरक्षा योजना** के अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है।
- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ योजना प्रभावी ढंग से लागू की गई है।

शैक्षिक अवसरों में वृद्धि

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** योजना के तहत बालिकाओं की विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ी है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक अनुपात में संतुलन की दिशा में सुधार देखा गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण

- **महिला स्वयं सहायता समूहों** के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधन प्राप्त हुए हैं।
- **Sukanya Samridhi Yojana** ने ग्रामीण परिवारों को बालिकाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी है।

चुनौतियाँ (Challenges)

1. **सूचना की कमी** – अनेक महिलाएँ योजनाओं की जानकारी से वंचित हैं।
2. **लाभ वितरण में असमानता** – जाति, वर्ग व क्षेत्रीय असमानता के कारण योजनाओं का लाभ सब तक नहीं पहुँचता।
3. **प्रशासनिक अक्षमता** – कई बार योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता।

सुझाव (Suggestions)

- महिलाओं को योजनाओं के बारे में जागरूक करने हेतु **स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम** चलाए जाएं।
- **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं** को बेहतर प्रशिक्षण और मानदेय दिया जाए।
- योजनाओं के **क्रियान्वयन की निगरानी** हेतु ग्राम स्तरीय समितियाँ गठित की जाएँ।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सूचना केंद्र** स्थापित किए जाएँ ताकि महिलाएँ योजनाओं के बारे में जान सकें।
- **SHG नेटवर्क को मजबूत** किया जाए ताकि वे योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सहभागी बनें।

- **डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम** के ज़रिए योजनाओं की निगरानी की जाए।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

डेटा विश्लेषण स्पष्ट करता है कि महिला एवं बाल विकास योजनाएँ ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलने में सहायक रही हैं। इन योजनाओं ने स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यदि इन्हें बेहतर क्रियान्वयन, समुदाय की भागीदारी और स्थानीय निगरानी के साथ जोड़ा जाए, तो ग्रामीण जीवन में और अधिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन योजनाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हालांकि, प्रभावी क्रियान्वयन और जागरूकता बढ़ाने के साथ इन योजनाओं की पहुँच और प्रभाव को और बेहतर किया जा सकता है।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में **कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी** हुई है।
2. **बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा** को लेकर सामाजिक मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है।
3. योजनाओं ने **आर्थिक आत्मनिर्भरता** को प्रोत्साहन दिया है।
4. फिर भी कुछ क्षेत्रों में **जानकारी की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ और योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति** एक चुनौती बनी हुई है।

संदर्भ (References)

1. Ministry of Women and Child Development, Government of India. www.wcd.nic.in
2. National Family Health Survey (NFHS-5), 2021. International Institute for Population Sciences (IIPS).
3. Planning Commission (2013). *Evaluation Study on ICDS Scheme*.
4. UNICEF India (2020). *Annual Report on Child Nutrition and Health*.
5. Government of India (2018). *National Nutrition Mission: Guidelines and Reports*.
6. World Health Organization (WHO), *Maternal Mortality Reports – India, 2022*.
7. Press Information Bureau (2020). “Achievements of Beti Bachao, Beti Padhao Scheme”.



8. Ministry of Women and Child Development, Government of India – <https://wcd.nic.in>
9. National Family Health Survey (NFHS-5), IIPS, Mumbai, 2021
10. NITI Aayog – Evaluation Report on POSHAN Abhiyaan (2022)
11. Press Information Bureau (2021), Reports on Sukanya Samridhi Yojana
12. World Bank (2020), “Empowering Rural Women through SHGs in India”
13. Ministry of Rural Development (MoRD), SHG Progress Reports
14. UNICEF India, Annual Child Health and Nutrition Report (2022)